fact that the condition is favourable for a fruitful dialogue with Indonesia? If so, may I know whether, without waiting for your going there, yourself, much later, the Government will invite a delegation from Indonesia to visit the refugee camps there and have a talk with them?

MR. SPEAKER: This question does not arise out of this. Let it be left to him. I am sorry.

SHRI SAMAR GUHA: This is a relevant question, Sir.

MR. SPEAKER: I am sorry. I am not going to allow it. We have not also been able to cover the normal number of questions since the last few days.

ग्राम्य क्षेत्रों में नियन्त्रित मूल्य पर मिट्टी के तेल की बिक्री

* 1518. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री बी० आर० शुक्ल :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मिट्टी के तेल के मूल्य को नियंत्रित करने और ग्राम्य क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की नियंत्रित मूल्य पर बिक्री सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को अनुदेश दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI P. C. SETHI): (a) and (b). Under the Essential Commodities Act the State Governments have powers to fix the retail selling price of kerosene at individual locations, including in the rural areas, and also to take up all cases of violations of the Act in this regard. Attention of the State Governments has been drawn to these provisions of this Act, with the request that the instructions in this regard may be reiterated to the District officials. The results of the measures that the State Governments will be taking in this regard will, no doubt, be watched by them.

श्री विभूति मिश्र : मन्त्री जी बार बार कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेन्ट्स को इंस्ट्रक्शंस भेज दिये गए हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्या मन्त्री जी ने अपने यहां से कुछ लोगों को भेज करके देहातों में—खास तौर से बिहार में—यह दरियाफ्त किया है कि गांवों में निश्चित कीमत पर मिट्टी का तेल मिलता है या नहीं ? यदि मिलता है तो किस कीमत पर और यदि नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है और उसके लिए कौन जवाबदेह है ?

श्री पी०सी० सेठी : अध्यक्ष महोदय, पिछले एक दो महीने पहले जरूर यह शिकायत आई थी, जैसे उड़ीसा से, यू० पी० से कि मिट्टी का तेल वहां कम है क्योंकि रेलवे वैगन्स न मिलने की वजह से तेल कम पहुंचा था लेकिन उसके बाद हल्दिया-बरौनी पाइप लाइन से किरोसिन आयल पहुंचाने का प्रबन्ध किया गया है और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जहां तक बिहार का ताल्लुक है मई के अन्दर 9216 टन किरोसिन आयल बिहार में पहुंचा था लेकिन पाइप लाइन के जरिए जून, 1971 में 16281 टन किरोसिन वहां पर पहुंचा है। और उसके बाद फिलहाल किरोसिन की शार्टेज की कोई शिकायत वहां से नहीं आई है।

श्री विभूति मिश्र : मैं ने यह पूछा था क्या आपने किसी एजेन्सी को वहां भेज करके यह दरियाफ्त कराया था कि गांवों में मिट्टी का तेल मिलता है या नहीं और निश्चित कीमत पर मिलता है या नहीं लेकिन मंत्री जी ने इसका कोई जवाब दिया नहीं है। **(व्यवधान)** ...

श्री पी०सी० सेठी : मैं ने पहले ही बताया कि राज्यों के अन्दर जहांतक किरोसिन की प्राइसेज् को देखने का ताल्लुक है यह स्टेट गवर्नमेन्ट्स को ही देखना है कि वह उचित कीमत पर मिल रहा है या नहीं। हमारे पास जब किरोसिन की कमी की शिकायत आई तो जरूर हमने पता लगाया था कि किन किन इलाकों में कमी है और उसके बाद पाइप लाइन से किरोसिन पहुंचाने का काम किया जा रहा है

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष जी, आपके आसन के ऊपर "धर्म चक्र प्रवर्तनाय" लिखा हुआ है। आप संविधान के अन्तर्गत हम लोगो को मिनिस्टर से उत्तर दिलवाइये। मै यह जानना चाहता हू कि गावो मे जो मिट्टी का तेल जाता है वह किस कीमत पर बिकता है और वह वहा पर लोगो को मिलता भी है या नही ? इस बात का पता लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई एजेन्सी कायम की है—स्टेट गवर्नमेन्ट के अलावा ?

अध्यक्ष महोदय . यह धर्म चक्र इसलिए लिखा है कि आप भी मेरा कहना मानें। यह न हो कि घटी बजे उसको भी नही सुनना है और मै कहू कि क्वैश्चन आवर ओवर तो उसको भी नही सुनना है।

श्री पी० सी० सेठी मै ने तो अभी निवेदन किया कि जहातक राज्यो मे तेल की कीमत तय करने का सवाल है हम जो कीमत तय करते है वह बाम्बे कलकत्ता मे पोर्ट प्राइस पर तय करते है लेकिन उसके बाद ट्रान्सपोर्टेशन पर कितना खर्चा आया, स्टेट गवर्नमेन्ट्स का सेल्स टैक्स कितना है उसको जोडकर स्टेट गवर्नमेन्ट्स प्राइस निर्धारित करती है। इसके अलावा कन्ट्रोल आर्डर के मुताबिक किरोसिन बिके, यह काम भी स्टेट गवर्नमेन्ट्स का ही है। जहातक सप्लाई की कमी का ताल्लुक है उनको हम देखते है और पूरा करने की कोशिश करते है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नो का समय समाप्त।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Geneva type Conference on Laos

*1501. SHRI P. K. DEO : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2076 on the 14th June, 1971 and state the progress made so far in reconvening the Geneva type conference on Indo-China to consider the latest developments in Laos ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : The two co-Chairmen have not come to any agreement on reconvening the Geneva Conference

नगरों के विकास के लिये योजना

*1504 **श्री रामावतार शास्त्री** . क्या **निर्माण और आवास** मत्री यह बताने की कृपा करेगे कि

(क) क्या सरकार ने नगरो के विकास के लिये एक योजना बनाई है, और

(ख) यदि हा, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री आई० के० गुजराल) (क) और (ख). नगरो के विकास का योजनाए राज्य क्षेत्र मे है, तथा सबधित राज्य सरकारो द्वारा बनाई जाती हैं। तथापि, केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता की व्यवस्था के फलस्वरूप, देश के 52 नगरो के लिये विस्तृत विकास योजनाए तैयार की गई है।

भारत द्वारा दिये गये ऋणो को लौटाने से कुछ देशो का इंकार करना

*1506. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव** : क्या **विदेश** मत्री यह बताने की कृपा करेगे कि.

(क) क्या कुछ देशो ने हाल ही मे उन्हे भारत द्वारा दिये गये ऋणो को लौटाने से इकार किया है,

(ख) यदि हा, तो उन देशो के नाम क्या है , और

(ग) भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी, नही।

(ख) और (ग). प्रश्न नही उठते।